

प्रेस विज्ञप्ति।

दिनांक 24.10.2019

## BSNL और MTNL के रिवाइवल हेतु कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों पर BSNLEU की प्रतिक्रिया...

कल दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को सम्पन्न यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में BSNL और MTNL के रिवाइवल पैकेज को अनुमोदित कर दिया गया है और इसकी घोषणा भी माननीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एक प्रेस वार्ता में की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान माननीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि BSNL और MTNL राष्ट्र की रणनीतिक संपदा है और उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, विनिवेश भी नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य (third party) को सौंपा जाएगा। माननीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने प्रमुखता से यह भी कहा कि नैसर्गिक आपदाओं के समय, यह BSNL ही था जिसने राष्ट्र को और नागरिकों को अपनी सेवाएं दी है। माननीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने BSNL द्वारा सुरक्षा बलों के लिए संचार व्यवस्था की निर्मिति और उनके रखरखाव में BSNL की भूमिका के महत्व को भी रेखांकित किया है।

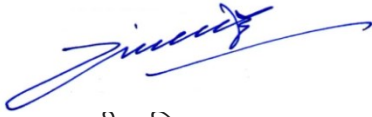
यूनियन कैबिनेट ने BSNL और MTNL को 4G स्पेक्ट्रम के प्रशासकीय आवंटन का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए इन दोनों ही PSUs में सरकार द्वारा पूंजी डाली जाएगी। यहां यह बताना जरूरी होगा कि विगत कुछ वर्षों से BSNL को 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने की यूनियन्स और एसोसिएशन्स की सबसे प्रमुख मांग रही है। BSNL के लिए समान कार्यस्थिति (level playing field) हेतु BSNL के एग्जीक्यूटिव व नॉन एग्जीक्यूटिव ने कई बार संघर्ष किया है, हड़तालें की हैं और दंडात्मक कार्यवाही का सामना भी किया है। कर्मचारियों की इस मांग को प्रभावशाली रूप से लेने और उसका कैबिनेट से अनुमोदन कराने के लिए BSNLEU, श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय संचार एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का आभार व्यक्त करती है। BSNLEU सभी कर्मचारियों को भी इस मौके पर, इस उल्लेखनीय (significant) उपलब्धि के लिए बधाई देती है। BSNLEU आम नागरिकों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन्होंने BSNL को 4G स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए जबरदस्त रूप से (overwhelmingly) सहयोग किया।

BSNLEU और कुछ अन्य यूनियन्स व एसोसिएशन्स के विरोध के बावजूद कैबिनेट द्वारा BSNL में VRS लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बंध में, BSNLEU यह ध्यान में लाना चाहेगी कि, यह तर्क सही नहीं है कि BSNL अपनी विशाल वर्कफोर्स की वजह से घाटे की स्थिति में पहुंचा है। इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इसी BSNL ने 2004-05 में रु 10,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था, जबकि उस समय आज की तुलना में कर्मचारियों की संख्या 1 लाख अधिक थी। साथ ही, यह तुलना करना भी सही नहीं होगा कि निजी कंपनियां अपनी कुल कमाई का केवल 5% ही वेतन पर खर्च करती है, जबकि इस हेतु BSNL द्वारा 70% खर्च किया जाता है। निजी कंपनियां अपना अधिकांश कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवाती है, जिसका खर्च वेज बिल में परिलक्षित नहीं होता है। जबकि, BSNL के अधिकांश कार्य उसके अपने कर्मचारी करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स भी शामिल है।

VRS के माध्यम से छंटनी करने की बजाय यह ज्यादा बेहतर होगा कि जो राशि VRS लागू करने हेतु खर्च की जाएगी, वह BSNL नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए खर्च की जाए, जिससे कंपनी की स्थिति में कायापलट (turn around)की सुनिश्चितता होगी। यह भी ज्ञात हुआ है कि, सरकार के पास कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 58 करने का प्रस्ताव भी विचारणीय है। सभी प्रमुख यूनियन्स और एसोसिएशन्स इसके विरोध में हैं और BSNLEU सरकार से अनुरोध करती है कि वह इस तरह के निर्णय लेने की कोशिश न करें।

BSNL और MTNL द्वारा जारी किए जाने वाले रु 15,000 के बांड्स, जिसका उपयोग ऋण भुगतान और नेटवर्क विस्तार के लिए किया जाएगा, हेतु सरकार द्वारा सार्वभौम जमानत (sovereign gurantee) देने के निर्णय का BSNLEU स्वागत करती है। यूनियन कैबिनेट द्वारा BSNL और MTNL के विलय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है जिसके तहत MTNL, BSNL की अनुषंगी होगी। इस हेतु MTNL को डीलिस्ट करने के सरकार के निर्णय का भी BSNLEU स्वागत करती है। साथ ही, BSNLEU मांग करती है कि विलय के पूर्व MTNL को ऋण मुक्त कंपनी बनाया जाए।

यूनियन कैबिनेट ने BSNL और MTNL की रु 38,000 करोड़ की भूमि के आगामी 4 वर्षों में मुद्रीकरण का अनुमोदन किया है। BSNLEU मांग करती है कि इस मुद्रीकरण की प्राप्तियां पुनः BSNL और MTNL के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु उपयोग में लाई जाए। साथ ही BSNLEU यह भी मांग करती है कि प्रस्तावित मुद्रीकरण के तहत BSNL और MTNL की जमीनें औने पौने दामों में नहीं बेची जा रही है, यह सुनिश्चित किया जाए।



पी.आभिमन्यु,  
महासचिव,  
BSNL एम्प्लॉईज यूनियन,  
मोबाइल न. 09868231113